

‘कांग्रेस ने सांप्रदायिक एजेंडा के तहत वंदे मातरम् के संक्षिप्त संस्करण को राष्ट्र गीत बनाया’

संसद में वंदे मातरम् पर बहस की शुरुआत करते हुए प्र.मंत्री मोदी ने कांग्रेस पर वंदे मातरम् का अपमान करने का आरोप लगाया

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 दिसम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में ‘वंदे मातरम्’ की 150 वीं वर्षगांठ पर हुई चर्चा में कांग्रेस पर तीखा हमला किया और भारत के राष्ट्रीय गीत को विपक्षी पार्टी की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 50 साल पहले लगाए गए आपातकाल से जोड़ने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि उनके एक और पूर्ववर्ती, जवाहरलाल नेहरू, ने ‘वंदे मातरम्’ का विरोध करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना का अनुसरण किया था, क्योंकि यह “मुसलमानों को नाराज कर सकता था।” उन्होंने कहा, “जब ‘वंदे मातरम्’ को लिखे 100 वर्ष हुये थे, तब देश आपातकाल में फँसा हुआ था... जब यह अपने 100 वें वर्ष में था, तब संविधान का गला घोट दिया गया था।” प्रधानमंत्री ने कहा, “अब, 150 साल बाद, यह ‘वंदे मातरम्’ की महिमा

- प्र.मंत्री ने कहा, बकिम चंद्र ने जो वंदे मातरम् लिखा था उसके शुरुआती दो अंतरे राष्ट्र गीत में रखे गए, शेष 6 अंतरे हटा दिए गए, क्योंकि उसमें हिंदू देवियों, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का संदर्भ दिया गया था, यह कांग्रेस का सांप्रदायिक एजेंडा था।
- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 1875 में वंदे मातरम् की रचना हुई थी। अब इसकी 150वीं जयंती है. यह अच्छा अवसर है, इसकी महिमा बहाल करने का।

को बहाल करने का एक अच्छा अवसर है... जिसने हमें 1947 में स्वतंत्रता दिलाई थी।” उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में लिखे गए इस गीत की सराहना की, और कहा कि यह जल्द ही स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक नारा बन गया था। “हमने हाल ही में अपने संविधान की 75 वीं वर्षगांठ मनाई। देश ने सरदार वल्लभभाई पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई। हम गुरु तेग बहादुर जी का 350वें शहीदी दिवस भी मना रहे हैं। अब हम ‘वंदे मातरम्’ के

के तहत इसका अनादर किया था और इसे इसके संक्षिप्त रूप में देश का राष्ट्रीय गीत बना दिया था। इस विवाद के केन्द्र में इसके छः अन्तरे हैं, जिनमें चट्टोपाध्याय ने हिन्दू देवी दुर्गा, कमला (या लक्ष्मी) और सरस्वती का संदर्भ दिया था, और इन्हें भारत की संरक्षक के रूप में प्रस्तुत किया था। 1937 में, कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष उस समय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ने राष्ट्रीय समारोहों में इसके केवल पहले दो अन्तरे (स्टैन्डा) गाने का निर्णय लिया था। इसका तर्क यह था कि हिन्दू देवियों के सीधे संदर्भ मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों द्वारा अच्छी तरह से नहीं लिए गए थे; इन्हें “बहिष्कार योग्य” माना गया था। प्रस्ताव में लिखा था: “सभी बातों पर विचार करते हुए, समिति यह सिफारिश करती है कि जब भी ‘वंदे मातरम्’ राष्ट्रीय समारोहों में गाया जाए, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

–मुर्शिदाबाद के बाद, ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा हुई

यू.पी. के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तीखी प्रतिक्रिया की कि मस्जिद बनाने पर कोई आपत्ति नहीं है, पर, अगर यह मस्जिद बाबर के नाम पर बनाई जाती है तो सख्त आपत्ति होगी।

- श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 दिसम्बर। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की एक प्रतिकृति बनाने की योजनाओं ने भाजपा के बीच भारी हलचल मचा दी है, यह विवाद अब और बढ़ता हुआ दिख रहा है, जब ‘तहरीक मुस्लिम शब्बन’ नामक एक समूह ने हैदराबाद के ग्रेटर इलाके में बाबरी मस्जिद स्मारक बनाने की योजना की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में, निर्लंबित तृणमूल विधायक हुमायूँ कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले में पहले मुगल सम्राट बाबर के नाम पर मस्जिद का शिलान्यास करने के अपने निर्णय से विवाद खड़ा कर दिया। इस विवाद पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई, जिन्होंने कहा कि भाजपा न केवल इस निर्माण का विरोध करेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित

- हैदराबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का एलान करने वाले तहरीक मुस्लिम शब्बन के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने इस पर कहा, “किसी को भी बाबर के नाम पर आशंकित नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं कि अयोध्या मस्जिद के निर्माण में बाबर का कुछ पैसा लगा था। यह संभव है कि पुरानी बाबरी मस्जिद किसी स्थानीय व्यक्ति बाबर के नाम पर बनी हो। भाजपा व आरएसएस इस बात को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। बाबर का शासनकाल तो बहुत छोटा था।”

करेगी कि इसे जल्दी से तोड़ा जाए। “मस्जिद के निर्माण में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई इसे बाबर के नाम पर बनाता है, तो इसे मजबूत विरोध का सामना करना पड़ेगा।” पश्चिम बंगाल में अगले साल के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, और आस्था के मुद्दे पर भाजपा को यह मसला प.बंगाल में साम्प्रदायिक

सुनील शर्मा राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त



सुनील शर्मा

जयपुर, 8 दिसम्बर (कासं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सोमवार को आदेश जारी कर सेवानिवृत्त आई.ए.एस. सुनील शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने से 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, के लिए की गई है। ज्ञात रहे कि सुनील शर्मा इस साल अप्रैल में ही सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। शर्मा, वर्ष (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जापान में भारी भूकंप, सुनामी की चेतावनी

टोक्यो, 08 दिसंबर। जापान में सोमवार को भूकंप के भीषण झटके से कांप उठा। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई है। भूकंप के तुरंत बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। इस कारण जापान के उत्तर-पश्चिमी तट पर तीन मीटर (10 फीट) ऊंची सुनामी आ

- रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई है।

सकती है। मछुआरों और छोटी बोट को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। भूकंप का केंद्र मिसावा शहर से लगभग 73 किलोमीटर उत्तर-पूर्व की ओर स्थित था, जिसकी गहराई लगभग 53 किलोमीटर मापी गई। यह उथले श्रेणी का भूकंप माना गया, जो आमतौर पर अधिक तीव्र झटकों का कारण बनता है। जापान प्रशांत, फिलीपीन सागर, यूरेशियन और उत्तर अमेरिकी प्लेटों के संगम पर स्थित है।

‘सरकार ने वंदे मातरम् पर बहस इसलिए रखी क्योंकि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं’

प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि सरकार हमें अतीत में उलझाए रखना चाहती है और वर्तमान व भविष्य पर बात नहीं करना चाहती

- डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 दिसम्बर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने आज लोकसभा में वंदे मातरम् पर हुई बहस के दौरान, प्रधानमंत्री और भाजपा पर तीखा लेकिन चुटीला वार किया और प्रधानमंत्री की नेहरू पर बार-बार की जाने वाली आलोचना पर कड़ा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान जितना समय जेल में बिताया था, वह लगभग उतना ही है, जितना समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सर्वोच्च पद पर बिताया है। वे वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर हो रही विशेष चर्चा में बोल रही थीं। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को सुझाव दिया कि वे जवाहरलाल नेहरू के लिए की गई सारी आलोचनाओं और अपमानों की एक पूरी सूची बना लें।

उन्होंने कहा, “चाहे वे 999, हों या 9,999-आप एक सूची बना लीजिए, और फिर हम तय कर सकते हैं कि इस पर कब चर्चा करनी है, जैसे हम वंदे मातरम् पर 10 घंटे, बहस कर रहे हैं। जितनी देर आप चाहें, उतनी देर हम बहस करने को तैयार हैं। लेकिन संसद के कीमती समय का इस्तेमाल उस काम के लिए होना चाहिए, जिसके लिए लोगों ने हमें चुना है। एक बार और हमेशा के लिए, इस अध्याय को बंद कर दें।” उनके इतना कहते ही विपक्षी सांसदों की ओर से जोरदार करल-ध्वनि हुई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, नेहरू नौ बार जेल गए और कुल मिलाकर 3,200 से अधिक दिन, यानी लगभग नौ वर्ष, जेल में रहे।

- प्रियंका गांधी ने कहा, भारत के पहले प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने कहा था, वंदे मातरम् पर विवाद साम्प्रदायिक ताकतों ने गढ़ा था।
- प्रियंका ने अपने तर्क के पक्ष में नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच लिखी गई चिट्ठियों का उल्लेख किया। गुरुदेव टैगोर ने लिखा था, जिन दो पदों का हमेशा गायन होता रहा है, वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें शेष गीत से अलग करने में कोई समस्या नहीं है और आज़ादी के आंदोलन में सभी इन दो पदों को ही गाते थे।
- टैगोर ने यह भी लिखा था कि इस गीत में बाद के जो पद हैं, उन्हें उस दौर के माहौल को देखते हुए सांप्रदायिक कहा जा सकता है।

प्रियंका गांधी ने आगे कहा, “देश सुन लेगा कि इंदिरा जी ने क्या किया,

राजीव जी ने क्या किया, वंशवादी राजनीति क्या है, नेहरू की क्या गलतियाँ थीं-आइए, इन सब पर बात कर लेते हैं और फिर इसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। फिर हम बेरोजगारी और महँगाई पर बात कर पाएँगे।” उनके इस बयान पर भी विपक्षी बेंचों ने जोरदार करल-ध्वनि की।

इससे पहले, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने वंदे मातरम् पर यह बहस अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए आयोजित की है। प्रियंका ने कहा, “यह बहस इसलिए करवाई जा है, ताकि जनता का ध्यान भटक गया जा सके, क्योंकि यह सरकार मौजूदा हालात की सच्चाई छिपाना चाहती है।”

वायनाड की सांसद ने यह भी सवाल उठाया कि संसद में वंदे मातरम् पर बहस की जरूरत ही क्या है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि यह गीत “देश के हर हिस्से में जीवित है और सम्मानित है।” उन्होंने कहा कि सरकार वंदे मातरम् पर चर्चा इसलिए चाहती है, क्योंकि जल्द ही बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। सरकार चाहती है कि हम अतीत में उलझे रहें, क्योंकि वह वर्तमान और भविष्य पर बात करना नहीं चाहती।” प्रियंका गांधी वाड़ा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस प्रकरण को गलत रूप में पेश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नेहरू, जो उनके परदादा और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ने वंदे मातरम् को लेकर हुए उस विवाद को “सांप्रदायिक ताकतों द्वारा खड़ा किया गया विवाद” कहा था। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गोवा अग्निकांड के आरोपी थाइलैंड फरार

गोवा, 08 दिसंबर। गोला क्लब हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। गोवा अग्निकांड के आरोपी थाईलैंड भागने में कामयाब हो गए हैं। अब गोवा पुलिस ने सीबीआई के जरिए इंटरपोल से मदद मांगी है। जिस

- गोवा पुलिस ने यह जानकारी दी। दोनों आरोपी सौरभ और गौरव भाई हैं तथा उस बार के मालिक हैं, जहां हादसा हुआ।

दिन घटना हुई, उसी दिन आरोपियों ने मुंबई से फुकेट (थाईलैंड) की फ्लाइट पकड़ी और भारत से बाहर भाग गए। डीजीपी गोवा आलोक कुमार के अनुसार ये खबर निकलकर सामने आई है। ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन से से जानकारी मिली कि दोनों मालिक आग लगने के तुरंत बाद 7 दिसंबर को सुबह 05.30 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वन रक्षक भर्ती का इनामी फरार आरोपी गुजरात से गिरफ्तार

जयपुर, 8 दिसम्बर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक मामले में पचास हजार रुपये के इनामी फरार आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी वन रक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक करने में अहम कड़ी है। गैंग के लोगों ने किन-किन लोगों को पेपर बेचा और कहाँ से लीक पेपर मिला, एसओजी की टीम यह पृष्ठताछ करने में जुटी है। एसओजी एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि ‘फरार आरोपी जबराम को

- एसओजी को आशा है कि इससे पूछताछ में यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि लोक पेपर कहाँ से हासिल किया तथा किस-किस को बेचा।

गुजरात से पकड़कर बांसवाड़ा लाया गया है और अब उससे पूछताछ की जाएगी।

एसओजी की पूछताछ के बाद सामने आएगा कि परीक्षा का पेपर लीक गैंग ने कहाँ से हासिल किया था और किन-किन लोगों को परीक्षा का पेपर बेचा गया था। आरोपी जबराराम सरकारी शिक्षक है और वनरक्षक भर्ती (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इंडिगो ही नहीं सभी भारतीय एयरलाइन्स बारूद के ढेर पर काम कर रही हैं

एक छोटी सी गलती, चिंगारी का काम करती है, पूरे सैक्टर को ढेर करने में

- एयरलाइन्स को टाइट बजट में काम करना होता है. हवाई जहाज़ के पेट्रोल पर भारी टैक्स है. हवाईअड्डों की क्षमता बहुत सीमित ही नहीं कम है. सैक्टर का संचालन करने वाले रेग्युलेटरी ढांचे का काम करने का तरीका अनिश्चित सा, लगभग मनमर्जी से चलने वाला लगता है।
- इंडिगो एयरलाइन्स के अनुभव ने यह जता ही दिया कि जब केवल एक्सपेंशन पर भारी जोर हो तो सिस्टम इतना नाजुक हो जाता है कि किसी भी दिक्कत से जूझकर, उसका सामना करके आगे बढ़ने की क्षमता उसमें नहीं रह जाती और तूफान तो दूर की बात है, हवा का झोंका ही ताश् के पत्ते के किले को ढहा देता है।
- सैक्टर को सुव्यवस्थित चलाए रखने के लिए गठित “रैग्युलेटरी सिस्टम” (नियंत्रक व्यवस्था) का रूख प्रतिक्रियात्मक है न कि दुर्घटना से पहले, दुर्घटना रोकने का इंतज़ाम करने वाला।
- इस सैक्टर का आधारभूत ढांचा- रनवे, पार्किंग स्थल, गेट्स, एरोब्रिज तथा ग्राउंड हैंडलिंग साधन इतने सीमित हैं कि किसी एक में कुछ गड़बड़ी हुई तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है।

‘इंडिगो संकट के झटके बिहार की सरकार में भी महसूस हुए

नीतीश की पार्टी जद (यू) ने पुरजोर ढंग से मांग उठाई की इंडिगो की “दिन दहाड़े डकैती” के खिलाफ सख्त और तुरंत कार्यवाही करे सरकार

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 दिसंबर। इंडिगो एयरलाइंस में चल रहे संकट ने सत्ताधारी एनडीए में अप्रत्याशित राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है, जिसमें गठबंधन सहयोगी हवाई उड़ानों की किराया वृद्धि और देशभर में व्याप्त संकट के चलते सार्वजनिक रूप से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इस स्थिति ने मोदी सरकार को असामान्य रूप से रक्षात्मक स्थिति में ला दिया है, क्योंकि प्रमुख सहयोगी तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग कर रहे हैं और निजी एयरलाइनों पर “दिनदहाड़े लूट” करने का आरोप लगा रहे हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे एक वरिष्ठ जदयू नेता ने बुधवार को इंडिगो के दफ्तर के बाहर धरना देने की धमकी दी, एयरलाइन पर अफरातफरी के बीच यात्रियों का शोषण करने का आरोप लगाया। उनका यह

- जद (यू) नेता व एनडीए के जाने माने चेहरे के.सी. त्यागी ने एक व्यक्तिगत जानकारी देकर और हड़कंप मचा दिया कि “उन्हें अपनी बेटी के दिल्ली-मुंबई टिकट के लिए इकतालीस हजार का नाजायज़ भुगतान करना पड़ा। त्यागी ने एयरलाइन्स से यह राशि लौटाने की मांग की तथा केन्द्रीय सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की “डिमांड” उठाई।
- त्यागी के अनुसार, यह मार्केट प्राइसिंग” नहीं है, बल्कि संकट के नाम पर शोषण है।
- पहली बार सरकार को विरोध का सामना विपक्ष की ओर से ही नहीं, अपने सहयोगी पार्टी की तरफ से करना पड़ रहा है।

आक्रोश एनडीए के भीतर गहरी निराशा को दर्शाता है, जो, साक्षेदारों के अनुसार, नागरिक विमानन क्षेत्र में शासकीय और नियामक विफलता का परिणाम है। इस दबाव को और बढ़ाते हुए, वरिष्ठ जदयू नेता और एनडीए का प्रमुख

चेहरा के.सी. त्यागी ने सरकार को एक व्यक्तिगत खुलासा करके चौंका दिया कि उन्हें अपनी बेटी के दिल्ली-मुंबई टिकट के लिए 41,000 रुपये की भारी राशि का भुगतान करना पड़ा। इसे “पूर्णतया लूट” बताते हुए, त्यागी ने

एयरलाइन से तत्काल रिफंड की मांग की और केन्द्र से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। “यह बाजार मूल्य निर्धारण नहीं है। यह संकट के नाम पर शोषण है”, त्यागी ने पार्टी के सहयोगियों से कथित तौर पर कहा, यह संकेत देते हुए कि नाराजगी न तो प्रतीकात्मक है और न ही राजनीतिक रूप से मंचित। अंदरूनी सरकार सूत्र इस विवाद पर चुपपी साधे हुए हैं, जबकि इस घटना ने केन्द्र के संकट प्रबंधकों के लिए एक अजीब और असहज स्थिति उत्पन्न कर दी है, जो पहले ही विमानन क्षेत्र में एक प्रमुख निजी एयरलाइन पर अत्यधिक निर्भरता के कारण आलोचना का सामना कर रहे हैं। मोदी सरकार कई मोर्चों पर समस्याओं का सामना कर रही है, यात्रियों के गुस्से और किराए के उतार-चढ़ाव से लेकर नियामक निगरानी, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)